

अच्छा व्यवहार  
करोड़ों दिलों  
को खरीदने की  
ताकत रखता है।  
- अज्ञात



## बेहाल हैं कामगार

डायमंड नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के प्रवासी कामगार 10 अप्रैल के बाद से यह कहकर सड़कों पर उतर रहे हैं कि जब यहां दो वक्त भर पेट भोजन भी नहीं दिया जा सकता तो हमारे लिए अपने गांव जाने का इंतजाम कर दिया जाए।

दिलीप लाल।

जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी? मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। आरिफ शफीक की ये लाइनें शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अब उलटी पड़ने लगी है। जिस शहर ने उन्हें ठिकाना दिया था, अब उसी शहर में उन्हें भूख पेट जीना पड़ रहा है। यह हाल तो देश के लगभग सभी शहरों का है, पर यहां बात दक्षिण गुजरात के सूरत शहर की हो रही है। डायमंड नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के प्रवासी कामगार 10 अप्रैल के बाद से यह कहकर सड़कों पर उतर रहे हैं कि जब यहां दो वक्त भर पेट भोजन भी नहीं दिया जा सकता तो हमारे लिए अपने गांव जाने का इंतजाम कर दिया जाए।

सूरत में इस समय 10 लाख से ज्यादा

प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें आधे से अधिक यूपी और बिहार के हैं। बाकी एमपी, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से हैं। ये सब मुख्यतः आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वीविंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी और डाइंग-प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में ये लोग सूरत के मार्केटों में भी काम करते हैं। यहां कुल 165 मार्केट हैं और एक मार्केट में औसतन डेढ़ से दो हजार दुकानें हैं।

सवाल यह है कि ये पर-प्रांतीय (प्रवासी) कामगार जो अमूमन दो-दो, तीन-तीन साल पर घर जाया करते थे, ऐसा क्या हो गया कि वे एक महीने में ही परेशान हो गए और घर जाने के लिए बेचौन हो उठे? इन प्रवासी कामगारों का सब्र टूटने के दो-तीन बड़े वाजिब कारण हैं। ज्यादातर



कामगार खाने भर का पैसा रखकर पूरी पगार घर भेज देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यहां पगार बांटने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि लॉकडाउन में इनके हाथ खाली हो गए। ज्यादातर कंपनियों में 5 से 7 तारीख तक पगार मिलती है और 25 से 27 तारीख के बीच में खर्ची (खोराकी) दी जाती है। खर्ची पगार की एक चौथाई होती है। खर्ची भर में ही ये गुजारा कर लेते हैं और 75 फीसदी सैलरी बचाकर घर भेज देते हैं। 21 मार्च को जनता कर्फ्यू था और 24 को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई। नतीजा यह हुआ कि सैलरी इनके पास थी नहीं और खर्ची इन्हें मिली नहीं। सारी उम्मीद लॉकडाउन की अगली सुबह यानी 15 अप्रैल पर टिकी हुई थी, वह भी टूट गई।

कुछ मालिकों ने कुछ दिनों तक खाने-पीने का प्रबंध किया, अब उन्होंने अपनी मजबूरी जताकर हाथ खींच लिया है। एनजीओ और कुछ धार्मिक संस्थाओं की ओर से अब भी खाने का प्रबंध किया जा रहा है, पर ज्यादातर लोगों को एक दिन मिलता है तो दूसरे दिन नहीं मिलता और कभी भर पेट मिलता है तो कभी आधा पेट ही रहना पड़ता है।

जो बड़े कारोबारी हैं और जिनमें संवेदनाएं भी हैं उन्होंने तो अपने कामगारों को संभाल लिया है, पर ऐसे लोग कम हैं। ज्यादातर कारोबारियों पर अपने भविष्य की चिंता भारी पड़ रही है। उनका कहना है कि कच्चा माल गोदाम में पड़ा है, डिलिवरी नहीं हो पाई है। सो पार्टी से पैसा नहीं मिला है।

## आकाशगंगा

अशोक वोहरा। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, यह बात दावे के साथ कोई

500 साल पहले कह दी गई थी।

लेकिन सूरज किस चीज के इर्द-गिर्द घूमता है, इसे लेकर

आज भी खोजबीन जारी है।

आकाशगंगा की यह धुरी धनु राशि में है और यह कोई बहुत भारी, अदृश्य चीज है, इसपर खगोलशास्त्रियों में सहमति है। आम समझ के मुताबिक यह सूरज का 40 लाख गुना वजनी एक ब्लैक होल है, जिसके घूर्णन का हिसाब लगाया जाना बाकी है। सैजिटेरियस ए स्टार नाम वाली इस चीज से जुड़ी जानकारी हम इसके करीबी तारे एस-2 का गुणधर्म देखकर हासिल करते हैं, क्योंकि 26 हजार प्रकाश वर्ष दूर के उस धुंधले इलाके में यही अकेला ऐसा पिंड है, जिस पर लगातार नजर रखी जा सकती है।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### छात्र संघ का चुनाव

शुरु से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। 70 के दशक में जब इमरजेंसी लगी, तब जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर छात्र और युवा आंदोलन में प्रमुखता से शामिल हो रहे थे। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन हुआ, बिहार से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लोकनायक जयप्रकाश की अगुआई में बड़ी संख्या में युवा और छात्र उस आंदोलन का मजबूत आधार बने हुए थे। आंदोलन व्यापक होता जा रहा था, पर अचानक देश में इमरजेंसी लगा दी गई। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो राजनीति का एक नया अध्याय शुरु हुआ। जनता पार्टी बनी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी तब छात्र राजनीति का केंद्र थी। जनता पार्टी तो बन गई थी, लेकिन जनता पार्टी में शामिल तमाम पार्टियों के अपने अलग-अलग छात्र संगठन थे। स्वाभाविक रूप से उन सबका आपस में विरोध रहने लगा। दिल्ली में आरएसएस का आधिकारिक स्टूडेंट फ्रंट एबीवीपी सक्रिय था। जनता पार्टी के जितने बाकी घटक थे उनके छात्र संगठनों की भी मौजूदगी थी, लेकिन एबीवीपी सबसे बड़ा संगठन था। इन सबके बीच समन्वय कैसे हो इस पर विचार हुआ। इस विचार-विमर्श का नतीजा यह निकला कि 1977 में जब छात्र संघ चुनाव हुए तो जनता पार्टी से जुड़े तमाम छात्र संगठन मिलकर चुनाव लड़े। डीयू में विजय गोयल के नेतृत्व में जनता पार्टी के छात्र संगठन ने जीत दर्ज की। उस वक्त रजत शर्मा जनरल सेक्रेटरी बने। छात्र संघ के उदघाटन में खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आए थे। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रेजिडेंट बना। लेकिन 1979 के चुनाव में फिर जनता विद्यार्थी मोर्चा ने चुनाव लड़ा और इस बार चारों सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद जनता पार्टी में विघटन शुरु हो गया। सरकार भंग हुई और लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर वापस आ गई।

डब्ल्यूएचओ के जरिए बहुत से देशों ने कोरोना की चुनौतियों को समझा है और उससे लड़ने का हौसला और तरीका हासिल किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसे समझने को तैयार नहीं हैं।

## ट्रंप के फैसले की आलोचना

मानव जोशी।

अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की फंडिंग रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका असर खुद अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप काफी पहले से डब्ल्यूएचओ पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन बीते मंगलवार को उन्होंने दो से तीन महीने के लिए इस संस्था की फंडिंग रोकने का फैसला सुना दिया। ध्यान रहे, डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 15 फीसदी हिस्सा अभी अमेरिका से ही आता है। ट्रंप का कहना है कि कोरोना महामारी के कुप्रबंधन और उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां छिपाने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका का आकलन किया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। चीन ने इसे अमेरिका द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करार देते हुए इस कदम को अनैतिक करार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की जंग में डब्ल्यूएचओ की कोशिशें काफी अहम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे वक्त में इस वैश्विक संस्था के संसाधनों में कटौती नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स ने इस



फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे समय पर, जब पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संकट चल रहा है, डब्ल्यूएचओ का पैसा रोकना खतरनाक है। संस्था के काम से कोरोना के प्रसार में कमी आ रही है। इसमें अडंगा लगाने की स्थिति में उसकी जगह कोई और संगठन नहीं ले सकता। सचाई यही है कि दुनिया को डब्ल्यूएचओ की जितनी जरूरत अभी है, उतनी पहले कमी नहीं थी।

कोरोना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जनजीवन को जिस तरह तहस-नहस किया है, उसकी खीझ ट्रंप एक ऐसे संगठन पर निकाल रहे हैं जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को और सबसे ज्यादा विकासशील देशों को है। डब्ल्यूएचओ के जरिए बहुत से देशों ने कोरोना की चुनौतियों को समझा है और उससे लड़ने का हौसला और तरीका हासिल किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसे समझने को तैयार नहीं हैं। अगर अमेरिका में कोरोना का कहर इतना ज्यादा है, तो इसके लिए ट्रंप प्रशासन की शुरुआती अकड़ भी कम जवाबदेह नहीं है। बेहतर होता कि ट्रंप इसे स्वीकार करते। बाकी मामलों में उन्होंने दुनिया की अगुआई की है, उसी तरह कोरोना से लड़ाई में भी विश्व का नेतृत्व करते। लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ पर गुस्सा निकालकर उन्होंने चीन को आगे आने का मौका दे दिया है।

संभव है, चीन इसकी फंडिंग बढ़ाए और कोरोना से वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से उसके हाथ में चला जाए। अभी अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सालाना 40-50 करोड़ डॉलर (30 से 38 अरब रुपये) की राशि देता है, जबकि चीन मोटे तौर पर सालाना 4 करोड़ डॉलर (लगभग तीन अरब रुपये) या उससे भी कम रकम अदा करता है। इस कदम से ट्रंप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब भी देर नहीं हुई है। बेहतर होगा कि वह अपनी भूल सुधार लें।

सूडोकू नवताल-5325		*****	
4	6	3	8 9 7
1			5 4
			8
4	5		8
2	5	4	6 1
3			1 7
	3		
5 9	7	2	6
7	6 4	3	9 2

सूडोकू नवताल-5324 का हल	
5	7 2 3 8 4 1 9 6
8	6 1 9 2 5 7 3 4
3	9 4 1 6 7 5 8 2
2	5 7 4 1 3 8 6 9
4	8 6 5 9 2 3 7 1
1	3 9 6 7 8 4 2 5
6	2 3 7 4 1 9 5 8
9	4 5 8 3 6 2 1 7
7	1 8 2 5 9 6 4 3

## अपना ब्लॉग ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं

मोहना। बैंक को ऋण चुकाना है। इन बातों में सचाई के अंश हो सकते हैं, पर इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि कामगारों के लिए अब एक-एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। उन्हें बीमारी और भूख दोनों सता रही हैं। वे आखिर करें तो क्या करें! 15 अप्रैल को सूरत के वेडरोड इलाके में लगभग 1000 एंब्रॉयडरी कारीगर सड़कों पर उतर पड़े। इनकी शिकायत थी कि इन्हें खाना नहीं मिल रहा है। जो राशन दिया जा रहा है वह खाने लायक नहीं है। आसपास कुछ दुकानें खुली हैं तो वे डेढ़ गुना कीमत वसूल रही हैं। ऐसे में गुजारा कैसे हो? सूरत के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों की नौ यूनिटें हैं। इनमें से कुछ ने स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि मजदूरों के लिए गांव लौटने की व्यवस्था की जाए। हालांकि इसे वर्तमान परिस्थिति के लिए अनुचित बताकर प्रशासन ने उनके खाने-पीने का इंतजाम बेहतर करने का आश्वासन दिया है।

